International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 1, January- 2022
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

नवीन नेपाली सं वधान और असहमति के मुद्दे

श्वेता सिन्हा
अतिथि सहायक प्राध्यापक
किसान कॉलेज, सोहसराय, नालंदा

सारांश: देश की शासन-व्यवस्था को चलाने के लए जरूरी मूलभूत आदर्शों और नियमों के लए राष्ट्रीय सहमति से नि र्मत कानूनी दस्तावेज को सं वधान कहा जाता है। सहमति पर आधारित होने की वजह से यह लोगों को आपस में जोड़ता है और उनके बीच एक मजबूत संबंध तैयार करता है। तभी राष्ट्रीय एकता और अखंडता अक्षुण्ण रह पाती है। ले कन नेपाल के वर्तमान सं वधान के लागू होने के बाद ऐसे कई मुद्दे उभरकर सामने आए हैं, जिन पर देश के अलग-अलग समुदायों का दृष्टिकोण सर्फ भन्न ही नहीं अ पतु वरदोही है, जो कसी भी नव- लोकतान्त्रिक देश के ले अच्छी बात नहीं काही जा सकती है। देश के द क्षण रहनेवाले और बहुसंख्यक मधेशी लोगो अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं। देश की धर्मनिरपेक्ष छ व से कुछ लोगों को तकलीफ है। देश का के ही एक हिस्से में शो षत और उपे क्षत होने का भाव घर करता जा रहा है और उनकी निष्ठा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देश के अंदर की असहमति का असर वैदे शक और पड़ोसी सम्बन्धों पर भी पद रहा है। ये सभी संकेत बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। दुखड़ायी तथ्य यह है क इन आशंकाओं और असहमतियों के निवारण की कोई वश्वसनीय को शश होती हुई नहीं दीख रही है। ऐसे में नेपाल के सामने बड़ी समस्या न खड़ी हो जाये, जो भारत जैसे पड़ोसी के लए खतरनाक बात होगी। प्रस्तुत आलेख में नेपाल के नवीन सं वधान और उससे जुड़ी असहमति के मुद्दों का अध्ययन करता है।

कुंजी शब्द: असहमति, नवीन सं वधान, नेपाल, लोकतन्त्र, मधेशी, एकता-अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 1, January- 2022
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

प्रस्तावना:

सतंबर **2015** में तत्कालीन राष्ट्रपति रामबरन यादव ने नवनि र्मत नेपाली सं वधान के लागू होने की घोषणा की। **1996** से ही नेपाल माओवादी हिंसा से जूझ रहा था और अगले दस वर्षों तक वह इसमें लगातार झुलसता रहा। ऐसे देश के लए एक लोकतान्त्रिक सं वधान का निर्माण बेशक एक शानदार उपलब्धि कही जा सकती है। ले कन इस सं वधान ने जीतने मुद्दों का समाधान कया, उससे ज्यादा मुद्दों को इसने जन्म भी दे दिया। देश के एक बड़े तबके मेन इसने हा शयाकरण का भाव भर दिया है। ऐसे कई मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं, जिन राष्ट्रीय सहमति का सर्वथा अभाव है।

धर्मनिरपेक्षता

धर्मनिपेक्षता के मामले पर बहस संवैधानिक सभा में निरंतर बनी रही। काफी लम्बे समय से हिन्दू राष्ट्र बने रहने के कारण नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना काफी चुनौती पूर्ण कार्य रहा। देश के तीन बड़े राजनीतिक दलों ने प्रारूप सं वधान में संयुक्त रूप से संशोधन प्रस्ताव रखा जिसमे धर्मनिपेक्षता को इस प्रकार परिभा षत कया गया 'प्राचीन काल से माने जा रहे धर्म और संस्कृति का संरक्षण तथा धा र्मक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता'। ले कन सं वधान में धर्मनिपेक्षता की इस प्रकार की परिभाषा रखने से वस्तुतः नेपाल को हिन्दू राष्ट्र बनाने की मंशा स्पष्ट झलकती है। प्राचीन काल के धर्म को संरक्षण देकर तीनो राजनीतिक दल अप्रत्यक्ष रूप से देश को हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहते है। व भन्न धा र्मक समूह, वं चत समूह और द लत समूह चाहते थे क धर्मनिरपेक्ष सं वधान बने जिससे उन्हें क रपंथी हिन्दू रिवाजों से उत्पन्न भेदभाव से मुक्ति मले। नेपाल की जनसँख्या के **3०** प्रतिशत संजातीय समूह भी धर्मनिरपेक्ष सं वधान के पक्ष में थे। वही दूसरी तरफ राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक जैसे दल और हिन्दू संगठन देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने के पक्ष में थे।

बहुत से मूलवासी और संजातीय समूह जीववादी है जो यह मानते है क हिन्दू धर्म के कारण उनकी पहचान फीकी पड़ रही है। एक धर्म के प्रभाव में वृ द्ध के फलस्वरूप करात धर्म में यकायक बढ़ोतरी हुई। **2००1** और **2०11** के जनगणना के आंकड़ो की तुलना करे तो हम देखेंगे क इस धर्म में उल्लेखनीय वृ द्ध हुई है। करात एक मूलवासी समूह है

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 1, January- 2022
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

जिसकी स्वयं की सभ्यता और इतिहास है, और यह एक धर्म के वर्चस्व से पी ड़त रहा है। वर्तमान धरमनिरपेक्षता के पहलू द्वारा सभी धर्मो और समुदायों के हितों की रक्षा सामान रूप से की जानी चाहिए तथा उन्हें अपना धर्म मानने और अवलंबन करने के लए समान अवसर प्रदान कये जाने चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रति क्रया

अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने नेपाल में नए सं वधान की घोषणा होने पर इसका स्वागत कया है। वश्व शक्तियों एवं संयुक्त राष्ट्र एवं यूरोपीय संघ जैसे समुदायों ने नेपाल में चल रहे आन्दोलन और संवैधानिक संकट को वार्ता द्वारा शांतिपूर्वक सुलझाने की मंशा जाहिर की है।

चीन के वदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा क, "चीन तहेदिल से नए सं वधान की घोषणा पर नेपाल को बधाई देता है तथा यह उम्मीद करता है क इस अवसर से नेपाल में राष्ट्रीय एकता, स्थिरता और वकास स्था पत होगा"। पा कस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नेपाल द्वारा नये सं वधान को ग्रहण करने के मौके पर बधाइयाँ दी और कहा क "हम नेपाल की सरकार और राजनीतिक दलों का इस उपलब्धि पर अ भनन्दन करते है। पा कस्तान को यह वश्वास है क नया सं वधान नेपाल में लोकतंत्र की नीवं को मजबूत करेगा।" बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नए सं वधान की घोषणा के मौके पर नेपाल के लोगों को बधाइयाँ दी।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने नेपाल में नए सं वधान की घोषणा पर कहा क "नेपाल सरकार को सभी नेपा लयों के वचारो और इच्छाओं को समाहित करने का सतत प्रयास करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित भी कया जाये क वैश्विक सद्धांतो और मानदंडो जैसे लैं गक समानता, धा र्मक स्वतंत्रता और नागरिकता का अ धकार को सं वधान में आ लंगनबद्ध कया जाये"। यूरोपीय संघ के प्रवक्ता ने कहा क, "यूरोपीय संघ यह उम्मीद करता है क सभी दल एकजुट होकर संवाद और सहमति के वातावरण में नेपाली नागरिकों के समक्ष आई चंताओं को सुलझाएंगे"। ब्रिटेन की तरफ से कहा गया क "हम इस प्र क्रया के अंतिम चरण का गहराई से अवलोकन कर रहे है। हमें आशा है है क यह नया सं वधान समावेशी, व्यापक रूप से सम र्थत तथा समानता के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करेगा"।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 1, January- 2022
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

इस अन्तर्राष्ट्रीय प्रति क्रया में अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन की प्रति क्रया कुछ हद तक भारत सर साम्यता रखती है।

भारत की प्रति क्रया

भारत नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना का समर्थक रहा है, बल्कि भारत की को शशों से ही नेपाल की राजनीतिक पार्टियाँ और माओवादी एक साथ आकार लोकतान्त्रिक सं वधान बनाने के लए तैयार हुए थे। ऐसे में भारत को नेपाल में सं वधान लागू होने से ख़ुशी होनी चाहिए थी, ले कन भारत की प्रति क्रया इस पर काफी तल्ख रही। इसकी मुख्य वजह मधे शयों का असंतोष है। मधेशी भारतीय मूल के है और वे भारत की सीमा से लगे इलाको में रहते है। खासकर बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों से मधे शयों के गहरे सम्बन्ध है। इस लए इन क्षेत्रों में अशांति का असर भारत पर भी पड़ेगा।

भारत की यह भी आपति रही क वर्ष **2००7** में अंतरिम सं वधान बनाते वक्त जो आश्वासन नेपाल की राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें दिए थे, उन्हें पूरा नहीं कया गया। तब यह तय कया गया था क सभी वर्गों और समूहों को इसमें उ चत प्रतिनि धत्व मलेगा।

भारत द्वारा नए सं वधान में संशोधन के सुझाव:

भारत ने नये सं वधान का अवलोकन करने के पश्चात् सं वधान में संशोधन के निम्न सात सुझाव दिए-

1. अंतरिम सं वधान का अनुच्छेद **63 (3)** के अनुसार चुनाव निर्वा चकाओं का गठन जनसँख्या, भौगो लकता और व शष्ट लक्षणों के आधार पर होगा, "और मधेश के मामले में यह जनसँख्या के प्रतिशत के आधार पर रहेगा"। इस प्रावधान के तहत मधेशी की जनसँख्या **5०** प्रतिशत से अ धक होती हैं और उन्हें संसद में **5०** प्रतिशत स्थान मलना चाहिए। बाद में नए सं वधान के अनुच्छेद **84** में इसका लोप कर दिया गया। भारत सरकार का मानना है क इसे पुनः स्था पत कया जाना चाहिए जिससे क मधे शयों को जनसँख्या के अनुपात में चुनाव निर्वा चकाओं में उनका स्थान मले।
2. अंतरिम सं वधान के अनुच्छेद **21** में व र्णत था क देश व भन्न समूहों को राज्य की संरचना में आनुपातिक समावेश के सद्धांत के आधार पर सहभागी

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 1, January- 2022
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

बनने का अवसर दिया जायेगा। नए सं वधान के अनुच्छेद **42** से आनुपातिक शब्द को हटा दिया, भारत का सुझाव है क इसे पुनः शा मल कया जाये।

3. नए सं वधान का अनुच्छेद **283** व र्णत करता है क राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायधीश, संसद के अध्यक्ष, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष, प्रान्तों के प्रमुख, मुख्यमंत्री, प्रांतीय सभाओं के अध्यक्ष, सुरक्षा वभागों के उच्च अ धकारी के पदों पर वे ही नागरिक आ सकते है जिन्हें वंशानुगत आधार पर नागरिकता मली है। यह प्रावधान उन बहुसंख्यक मधे शयों के साथ भेदभाव करता है जिन्होंने नागरिकता जन्म और देशीयकरण के आधार पर प्राप्त की है। भारत का सुझाव है क संशोधन द्वारा जन्म और देशीयकरण के आधार पर नागरिकता को भी इसमें शा मल कया जाये।
4. नये सं वधान का अनुच्छेद **86** कहता है क राष्ट्रीय सभा में **7** प्रान्तों से **8** सदस्य चुने जायेंगे तथा **3** सदस्यों को मनोनीत कया जायेगा। मधेशी दल चाहते है क राष्ट्रीय सभा में प्रान्तों की जनसँख्या के आधार पर प्रतिनि धत्व होना चाहिए, भारत इस बिंदु का समर्थन करता है।
5. पांच ववादास्पद जिले कंचनपुर, कैलाली, सुनसरी, झापा, मोरांग को पड़ौसी प्रान्त मधेश में शा मल कया जाना चाहिए।
6. अंतरिम सं वधान के अनुच्छेद **154** में व र्णत था क प्रत्येक **1०** वर्ष बाद चुनाव निर्वा चकाओ का प्रारूप प्रस्तुत कया जायेगा, जिसे नये सं वधान में **2०** वर्ष कर दिया गया। मधे शयों ने इस पर आपत्ति जताई जिसका समर्थन भारत ने कया।
7. नए सं वधान का अनुच्छेद **11 (6)** कहता है क यदि कोई नेपाली नागरिक वदेशी महिला से ववाह करता है तो उस महिला को संघीय कानून अनुसार देशीयकरण प्रदत्त नागरिकता मलेगी। मधे शयों की मांग है क देशीयकरण नागरिकता स्वतः ही होनी चाहिए, इस बिंदु का भी भारत समर्थन करता है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 1, January- 2022
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

भारतीय कदम पर नेपाल की प्रति क्रया

भारत द्वारा दिए गए इन सुझावों का नेपाल के राजनेताओं ने स्वागत नहीं कया। नेपाल के मी डया ने इसकी भर्त्सना करते हुए इसे भारत का अनावश्यक हस्तक्षेप कहा। नेपाल मूल की वदुषी मल्लिका शाक्य इस मसले पर कहती है क भारत का यह हस्तक्षेप नेपाली लोगों में ध्रुवीकरण को बढाता है और नेपाल की एकीकृत राजनीति में वरोधाभास पैदा करता है, अतः इस समस्या का हल नेपाल को स्वयं ही निकालने दे।

नेपाल वशेषज्ञ प्रो. एस. डी. मुनि इस बारे में कहते है क इस प्रकार के ध्रुवीकरण में भारत का कसी एक पक्ष का साथ देना न तो बु द्धमानी की नीति है और न ही प्रभावशाली कूटनीति है। नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओवादी) प्रमुख पुष्प कमल दहाल उर्फ प्रचंड ने कहा क उनका देश भारत से अच्छी दोस्ती चाहता है, ले कन नेपाल को कोई "यस मैन" के रूप में देखे यह मुम कन नहीं है। नेपाल में भारतीय सीमा से लगे अनेक हिस्सों में नये सं वधान को लेकर हिंसक प्रदर्शनों पर भारत द्वारा चंता जताये जाने के बाद प्रचंड ने यह बात कही। प्रचंड ने भारत की प्रति क्रया पर कहा नेपाली जनता के लंबे संघर्ष और ब लदान के बाद सं वधान आया है। नेपाल की सं वधान सभा शांति प्र क्रया के साथ जुडी थी। इस प्र क्रया में भारत का शुरू से ही सहयोग और सद्भाव रहा है। जव सं वधान बना तो हमें उम्मीद थी क भारत को भी अनुभूति होगी, वह इसका स्वागत करेगा ले कन यह दुर्भाग्यपूर्ण है क भारत को इसे लेकर कुछ आपत्तियां हैं, इसका हमें थोडा दुख है। काठमांडू पोस्ट ने इस बारे में कहा क " दिल्ली अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लए सीमा का उल्लंघन कर रही है जो क ठीक नहीं है। नेपाली अख़बार कांतिपुर ने लखा क 'ये समस्याएं हमारे लए सुलझाने के लए है, एक पड़ोसी देश इस चत्रण में आये और हमारी आंतरिक समस्याओं एवं चुनौतियों को सुलझाये यह हमें स्वीकार नहीं है।" द राइजिंग नेपाल ने लखा क,"भारत ने अभी तक नेपाल के नये सं वधान का स्वागत नहीं कया है, जो क भारत की सीमा से लगे तराई क्षेत्र में अस्थिरता लाएगा।"

नये सं वधान से असंतुष्ट मधे शयों के आन्दोलन के चलते सं वधान की घोषणा के तुरंत बाद ही भारत नेपाल सीमा पर अघो षत नाकेबंदी हो गई, जिससे नेपाल में खाद्य आपूर्ति एवं पेट्रो लयम उत्पादों की आपूर्ति बंद हो गई। नेपाल ने इसका आरोप भारत पर

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 1, January- 2022
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

लगाते हुए कहा क भारत यह दबाव जान बूझ कर बना रहा है। वही भारत का कहना है क इस प्रकार की आ र्थक नाकेबंदी की उसने कोई घोषणा नहीं की है। नेपाल के उपप्रधानमंत्री ने इस आ र्थक नाकेबंदी के मामले को संयुक्त राष्ट्र के महास चव बान की मून के सम्मुख भी रखा है। यह कदम दोनों देशों के मध्य अ वश्वास एवं कटुता को और गहरा करती है। यदि यह गतिरोध की स्थिति आगे बनी रही तो काफी उद्योग एवं कारोबार को बंद करना पड़ेगा जिसका नुकसान भारत को भी उठाना पड़ेगा। क्यों क खुली सीमा होने की वज़ह से दोनों देशों के मध्य व्यापार निर्बाध रूप से चलता है। अतः इससे पहले क भारत नेपाल सम्बंधो में कटुता और बढे, दोनों देशों को बिना समय गँवाए कूटनीतिक रास्ते से इस मसले का हल करना चाहिए।

वर्त्तमान गतिरोध का भ वष्य

नेपाल के पूर्व सं वधानों की रचना के दौरान ये देखा गया है क, जब कभी संजातीयता, शासन, भाषा और क्षेत्रीय समस्याओं को अनदेखा कया गया है, इसकी पुनरावृत्ति बाद में मुख्य मुद्दो के रूप में सामने होती है, जिसके कारण देश में जन आन्दोलन और क्रांति का जन्म होता है। नये सं वधान द्वारा स्थिरता लाने के लए, संवैधानिक सभा को देश में उठती मांगो और आवाजों को सुनना चाहिए था और उन्हें समाहित करना था।

भारत को जरुरत है क वह अपने कुटनीतिक द्रष्टिकोण को नरम रखे, अपने आपको सीमान्त समूहों और नेपाल सरकार के खेमे के साथ एक सार्थक संवाद के जरिये जोड़े। इस प्रकार से उप क्षेत्रीय एकीकरण मजबूत होगा, जिस पर भारत ने हमेशा से जोर दिया है। नेपाल का सं वधान नम्य है, इसमें संशोधन की गुंजाईश का क्षेत्र व्यापक है। राजनीतिक इच्छा द्वारा वर्तमान गतिरोध और संकट का एक ता र्कक हल निकाला जा सकता है।

ले कन मधेसी और द क्षणी नेपाल और कुछ पश्चिमी जिलों में थारू जातीय समुदाय नए सं वधान के खलाफ हैं क्यों क उनका मानना है क यह मधेसी और थारू जातीय समुदायों की ओर से उठायी गई चंताओं का समाधान करने के असफल रहा। भारत ने नेपाल में जारी हिंसा को लेकर चंता जताई है। भारत ने वदेश स चव एस. जयशंकर को

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 1, January- 2022
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

प्रधानमंत्राी नरेंद्र मोदी के दूत के तौर पर नेपाल भेजा गया था ता क नेपाली नेतृत्व से आग्रह कया जा सके क वह सभी पक्षों की चंताओं का समाधान करे। जयशंकर ने कल कहा था क सं वधान लागू होना खुशी का मौका होना चाहिए हिंसा का नहीं। बाद में नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने आंदोलनकारी मधेसी और थारू समूहों से अपील की थी क वे अपना आंदोलन वापस ले लें और बातचीत के लए आगे आएं। उन्होंने कहा था क सभी समस्याओं का हल समझौते और साथ काम करके कया जा सकता है।

नवीन सं वधान और नागरिकता का मुदा:

नेपाल में नागरिकता प्रमाणपत्र कसी भी नेपाली आदमी के लए सर्वा धक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है पर इसे पाना बड़ा ही कठिन है. एक अनुमान के मुताबिक देश में क़रीब बीस लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास ये दस्तावेज़ नहीं है इसका मतलब है क ये लोग नेपाल के निवासी हैं ले कन नागरिक नहीं. कई लोगों को भय है क नेपाल के नए सं वधान में ये नियम और कड़े कए जा सकते हैं. नागरिकता से संबन्धित इन प्रावधानाओं की वजह से कई लोग अजीब पेशोपेश में पड़ गए हैं। नेपाल के क्रकेट खलाड़ी शरद भेस्वाकर देश के बड़े खला ड़यों में से एक हैं. वो नेपाल की टीम की राष्ट्रीय टीम के खलाड़ी हैं ले कन देश के अ धकृत नागरिक नहीं हैं. उनका पूरा जीवन नेपाल में बीता है. उनकी माँ नेपाली हैं पर उनके पता भारतीय थे. नेपाल के कानून के मुताबिक उन्हें नागरिकता हा सल करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए थी. ले कन अभी तक नागरिकता हा सल करने की उनकी को शश नाकाम रही है. उनकी माँ भगवती छेत्री इस असहाय स्थिति पर कहती हैं, "मैं पछले आठ साल से नागरिकता प्रमाण पत्र लेने की को शश कर रही हूँ. साल भर में मैं जो भी बचाती हूँ वो सब इसी को शश में ख़र्च हो जाता है. अब तो बिना नागरिकता प्रमाण पत्र के कोई मकान भी कराए पर नहीं देता. मेरा तो चल गया पर मेरे बच्चों का क्या होगा बिना इसके वो कैसे अपनी रोज़ी रोटी कमाएंगे. शरद इस मुद्दे पर कहते हैं " ये बहुत ही लंबा कस्सा है. आठ नौ सालों से मैं इस जद्दोजहद में लगा हूँ. पर समस्या वहीं की वहीं है. कई बार ये मामला बेहद परेशान कर देता है." कुछ साल पहले नेपाल सरकार ने एक वशेष मामला मानते हुए उन्हें अंतरराष्ट्रीय मैचों में खेलने जाने के लए एक पासपोर्ट जारी कया था पर

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 1, January- 2022
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

शरद अभी भी नेपाली नागरिक नहीं हैं. बिना नागरिकता प्रमाणपत्र के वो बैंक में खाता नहीं खोल सकते, ड्राइ वंग लाइसेंस नहीं ले सकते और तो और उच्च शक्षा के लए प्रयास भी नहीं कर सकते. नेपाल नागरिकता अ धनियम **2006** के मुताबिक नेपाल में **16** साल की उम्र में कसी को भी नागरिक घो षत कया जा सकता है बशर्ते आवेदनकर्ता के माँ या पता ने उसके आवेदन पर हस्ताक्षर कए हों. ले कन इसके बावजूद पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को अपने बच्चों को नागरिकता दिलाने में काफी दिक्कत पेश आती है, खासकर वैसी स्थिति में जब पता न हों या फर पता नेपाल के नागरिक न हों.

महिलाएं अ धक परेशान

प्रारूप में कहते हैं क नेपाल में नागरिकता के लए माता और पता दोनों का नेपाली होना ज़रूरी है तभी कसी को नागरिकता मल पाएगी. कसी एक के नेपाली होने से काम नहीं चलेगा. संयुक्त राष्ट्र के मानवा धकार मामलों के समन्वयक रॉबर्ट पाईपर कहते हैं, "ऐसी समस्या वाले लोगों की संख्या संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों से कहीं ज़्यादा हो सकती है. नेपाल के चुनाव आयोग ने गाँवों में लोगों से बात की थी और **20** लाख से ज़्यादा लोग अपने नागरिकता प्रमाणपत्र नहीं दे पाए, उन्होंने शहर में लोगों से अभी बात ही नहीं की है." नेपाल के सं वधान सभा की सदस्य उषाकला राय कहती हैं " कई महिलाएं हिंसा और भेदभाव का शकार होती हैं. ख़ास तौर पर महिलाएँ जो काम काज के लए बाहर जाती हैं, जिनके पति उन्हें छोड़ चुके हैं या जिनका तलाक हो चुका है उनके और उनके बच्चों को नागरिकता से वं चत होना पड़ सकता है."

नेपाल में नागरिकता एक संवेदनशील मुद्दा है. नेपाल के सरकारी अ धकारियों और नेताओं को लगता है क उन्हें इस मामले में सख्त होना ही होगा क्यों क नेपाल तीन तरफ़ से भारत जैसे वशाल और बड़ी आबादी वाले देश से जुड़ा है. राजनेता कहते हैं क नए सं वधान में वो औरतों के खलाफ़ भेदभाव को दूर कर देंगे. संयुक्त राष्ट्र के अ धकारियों का कहना है क मामला दावे के उलट है. संयुक्त राष्ट्र के रॉबर्ट पाइपर कहते हैं क नए सं वधान के प्रारूप में नियम और सख्त हैं. पाइपर के अनुसार "प्रारूप में कहते हैं क नेपाल में नागरिकता के लए माता और पता दोनों का नेपाली होना ज़रूरी है तभी कसी

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 1, January- 2022
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

को नागरिकता मल पाएगी. कसी एक के नेपाली होने से काम नहीं चलेगा." नागरिकता नियम अभी पूरी तरह से तय नहीं हुए हैं ले कन लोगों में भय है क अगर प्रारूप में मौजूद प्रस्ताव मान लए गए तो लाखों लाख लोग मूलभूत अ धकारों से वं चत हो जाएँगें.

कोरोना संकट के बीच नेपाली नागरिकता के नए प्रावधानों का ऐलान

तीन भारतीय क्षेत्रों को अपने नए नक्शे में शा मल करने के कानून को पास करने के बाद 19 जून को नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की स चवालय बैठक में भारतीयों के लए नागरिकता कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी गई. टाइम्स नाउ के अनुसार, नेपाल सरकार द्वारा लाए गए संशोधन को सही ठहराने के लए नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने भारत के नागरिकता कानून का उदाहरण दिया. थापा ने घोषणा की क नए कानून के अनुसार, नेपाली नागरिक से शादी करने वाली कसी भी भारतीय लड़की को नागरिकता हा सल करने के लए सात साल का इंतजार करना पड़ेगा. उन्होंने इसके लए भारतीय कानून का हवाला दिया जिसके तहत कसी वदेशी नागरिकता वाले व्यक्ति को कसी भारतीय से शादी करने के सात साल बाद ही नागरिकता दी जाती है. हालां क, नेपाल के गृह मंत्री ने अपने बयान में इस तथ्य का उल्लेख नहीं कया क भारतीय नागरिकता कानून का यह प्रावधान नेपाली नागरिकों पर नहीं लागू होता है.

निष्कर्ष:

अंत में निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है क नेपाल का नवीन सं वधान निस्संदेह दशकों की माओवादी हिंसा से जूझ रहे हिलामायी देश के लए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके सहार इसने राजतंत्र से लोकतन्त्र का सफर तय कया है। ले कन सं वधान की एक बुनियादी शर्त यह होती है क यह राष्ट्रीय सहमति पर आधारित हो और वह सर्वग्राह्य हो। इस कसौटी पर नेपाली सं वधान पूरी तरह खरा नहीं उतरता है। इसने असहमति के कई बिन्दुओं को जन्म दिया है, जिसका समाधान पर ही नेपाल का भ वष्य टिका है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 1, January- 2022
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

संदर्भ:

1. **Sanjay Kumar, "Nepal Tests India's Much Touted Neighborhood Diplomacy", *The Diplomat*, September 26, 2015**
2. **Hari Phuyal, "Nepal's New Constitution: 65 Years in the Making", THE DIPLOMAT, 18 September, 2015,**
3. **http://thediplomat.com/2015/09/nepals-new-constitution-65-years-in-the-making/**
4. **Nepal enshrines the Right to Food in new constitution,**
5. **http://www.fao.org/news/story/en/item/334895/icode/**
6. अवधेश कुमार, "नेपाल का नया सं वधान भेदभाव पूर्ण", पीपुल्स समाचार, **September 27, 2015,**
7. **http://thediplomat.com/2015/09/nepal-tests-indias-much-touted-neighborhood-diplomacy/**
8. "भारत का "यस मैन" नहीं बनेगा नेपाल: प्रचंड", *खास खबर*, **September 22, 2015,**
9. **http://www.khaskhabar.com/picture-news/news-seeks-friendship-but-nepal-will-not-be-yes-man-of-india-prachand-1-13036.html**
10. **https://thewirehindi.com/127692/nepal-ruling-communist-party-amended-citizenship-law-for-indians/**